

## राज्य प्रायोजित साइबर हमले

### प्रलिस के लयल:

राज्य प्रायोजलतल हमले, [पेगासस सपाइवेयर](#), साइबर हमला, गोपनीयता उल्लंघन, [भारतीय साइबर अपराध समनवय केंद्र \(I4C\)](#), [साइबर सुरकषा](#)

### मेन्स के लयल:

पेगासस परयोजना और नगरानी में सुधार की आवश्यकता, सरकारी नीतयों और वभिन्न क्षेत्रों में वकलस के लयल हस्तकषेप और उनके डज़ाइन एवं कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हद्वि](#)

## चरचा में कयों?

हाल ही में Apple Inc. ने वपिक्षी नेताओं और पत्रकारों सहलत वयक्तयों को "राज्य-प्रायोजलतल हमलावरों के बारे में सूचलतल कयलल, जो उनके iPhones को दूरस्थ गतवधलयों के तहत **जोखमल में डालने की कोशशल कर रहे हैं**" ।

- ऐसा दूसरी बार हुआ है कल भारत में वपिक्षी राजनेताओं और नागरकल समाज के अभकलरत्ताओं को चेतावनी दी गई है कल **वेज़ासूसी के परयासों का नशलाना बने हैं** ।
- वर्ष 2021 में पेरसल स्थलतल [?] ने बताया कल [पेगासस सपाइवेयर](#), जो केवल इज़रायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा सरकारी एजेंसयों को बेचा गया था, का कथलतल तौर पर भारत में कई पत्रकारों, नागरकल समाज समूहों और राजनेताओं पर इस्तेमाल कयलल गया था ।

**नोट:** [साइबर हमला](#) कंप्यूटर ससल्टम, नेटवरक या डजलटल उपकरणों की सुरकषा में सेंध लगाने का एक दुर्भावनापूर्ण और जान-बूझकर कयलल गया परयास है, जसलका उद्देश्य संवेदनशील डेटा को चुराना, नुकसान पहुँचाना, बदलना या उस तक पहुँचाना, संचालन में बाधा डालना या डजलटल क्षेत्र में नुकसान पहुँचाना है ।

## राज्य प्रायोजलतल साइबर हमले:

- **परचय:**
  - राज्य-प्रायोजलतल साइबर हमले, जलन्हें राष्ट्र-राज्य साइबर हमलों के रूप में भी जाना जाता है, **अन्य देशों, संगठनों या वयक्तयों के खललाफ सरकारों या सरकारी एजेंसयों द्वारा संचाललतल या समर्थलतल साइबर हमले हैं** ।
  - चूँकल ये हमले कसलसी राष्ट्र-राज्य के वशलाल संसाधनों और कषमताओं द्वारा समर्थलतल होते हैं, इसललयल वे अपने उच्च स्तर के संगठन, जटललता और संसाधनशीलता से प्रतषलठलतल होते हैं ।
  - राज्य-प्रायोजलतल साइबर हमलों के उदाहरणों में स्टक्सनेट वरम शामिल है, जसलने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लकषलतल कयलल, वर्ष 2016 के अमेरकलली राष्ट्रपतल चुनाव में कथलतल रूसी हस्तकषेप एवं वर्ष 2017 वानाकराई रैनसमवेयर हमला, जो उत्तर कोरया से जुड़ा था ।
- **राष्ट्रीय सुरकषा पर परभाव:**
  - **डेटा चोरी:** राज्य-प्रायोजलतल हमलों से संवेदनशील राष्ट्रीय सुरकषा जानकारी, गोपनीय सैन्य सूचना और महत्त्वपूर्ण बुनयादी ढाँचा संबंधी डेटा की चोरी हो सकती है । इस तरह के उल्लंघन कसलसी देश की रकषा कषमताओं से समझौता कर सकते हैं ।
  - **आर्थकल परभाव:** परमुख उद्योगों और महत्त्वपूर्ण बुनयादी ढाँचे पर हमलों से आर्थकल नुकसान हो सकता है । उदाहरण के लयल ऊर्जा या वलतलतीय प्रणालयों में वयवधान के गंभीर आर्थकल परणलाम हो सकते हैं ।
  - **राजनीतकल परभाव:** साइबर हमलों का उपयोग जनता की राय में हेर-फेर करने, चुनावों को प्रभावलतल करने और राजनीतकल स्थरलता को कमज़ोर करने के लयल कयलल जा सकता है । दुष्प्रचार अभयलन तथा हैकगल के दूरगामी राजनीतकल परभाव हो सकते हैं ।

- राष्ट्रीय संप्रभुता: साइबर हमले किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकते हैं और अपने नागरिकों पर शासन करने तथा उनकी रक्षा करने की क्षमता से समझौता कर सकते हैं।

## ?????? (Pegasus):

### ■ परिचय:

- यह एक प्रकार का मैलेशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जिसे स्पाइवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये डिज़ाइन किया गया है और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है तथा इसे वापस रलि करने के लिये सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
- पेगासस को इज़रायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है जिसने वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था।
  - पेगासस संक्रमण को ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर तथाकथित "ज़ीरो-क्लिक" हमलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके सफल होने के लिये फोन के मालिक से किसी भी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है।

### ■ लक्ष्य:

- इज़रायल की नगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए एक फोन मैलवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया है।
- भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी और वपिक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके फोन पर इस स्पाइवेयर द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इज़रायल के NSO ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है।

### ■ साइबर सुरक्षा हेतु पहलें:

- भारतीय पहलें:
  - साइबर सुरक्षा भारत पहल
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC)
  - साइबर स्वच्छता केंद्र
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सर्ट-इन (Indian Computer Emergency Response Team- CERT-In)
- वैश्विक पहलें:
  - अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
  - साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय

## आगे की राह

- व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने तथा लागू करने की आवश्यकता है जो साइबर क्षेत्र में रक्षा एवं अपराध दोनों का समाधान करेंगी।
- सरकारी एजेंसियों के लिये घुसपैठ पहचान हेतु उन्नत प्रणाली, सुरक्षित नेटवर्क और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सहित साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।
- खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और राज्य-प्रायोजित खतरों पर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिये अन्य देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिये।